

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं• 36]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 9. 1978 (भावपद 18, 1900)

No. 36]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 9, 1978 (BHADRA 18, 1900)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it may be fled as a Separate Compilation.

विषय-सूत्री						
****	नुब् ठ		पुष्ठ			
भाग I—वण्ड 1—(रक्षा भंद्यालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंद्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमो, वितियमों तथा श्रादेशी और संग्रलों से सम्बन्धित श्रीधमूचनाएं भाग Ηखण्ड 2—(रक्षा मद्रालय को छोड़कर)	729	जारी ।कए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के प्रादेश, उप-नियम भादि सम्मिलित हैं) . भाग II – खण्ड 3 – – उप लण्ड (ii) – (रक्षा मंत्रातय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों ग्रीर (संघराज्य क्षेत्रों के प्रणाानों का	2069			
भारत भरकार के सहालयों और उच्चतम स्यायाला हारा ारी की गई घरफारी भक्तरा की नियक्तियों, पदीचित्यों, कृद्धियों स्रादि से सम्बन्धित ग्रांबनूचनाएं	1193	छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के भन्तर्गत बनाए और जारी किए गए श्रादेशश्रीर अधिसूचनाए	2395			
भेर्मा 1—वण्ड 3—रक्षा मजाउप द्वारा गारी की गई विधितर निजमी, विनिधमी, श्रादेशों श्रीर सवास्ये से उम्बन्धित ग्राधिसूचनाएं	9	भाग II—खण्ड 4रक्षा मंत्रालय द्वारा अधि- सूचित विधिक नियम और आदेश भाग III—खण्ड 1महालेखापरीक्षक, संघ लोक- सेवा आयोग, रेल प्रशासन, अच्च मंत्रालयों	207			
भाग I—-द्राण्ड 4रक्षा मत्राला द्वारा जारो की गई अफसरो की नियुवितयों, पदोक्षतियों,		भीर भारत सरकार के प्रधीत तथा तंत्रग्त कार्यालयो द्वारा जारी की गई क्रधिसूचनाएं	5109			
छुट्टि∓ो प्रादि से सम्बन्धित ग्रधिसूचनाए भाग II—खण्ड 1—ग्रधिनियम, प्रध्यादेण और	861	भाग III—ज्वण्ड 2—ः हस्य कार्यालयः, कलकत्ता द्वारा जारी की गर्ट अधिसूचनरण् प्रोर नोटिस	651			
विनियम भाग II—खम्ड 2—विधेयक ग्रीर विधेयकों सर्वधी	_	भाग III — क्षण्ड 3 — १६८ आयुक्ती द्वारा या उनके प्राधिकार त जारी की गई ध्रसिमूचनाएं	139			
प्रवर मर्मितियों की रिपोर्ट .	-	भाग III—-खण्ड 4विधिष्ठ निकासो प्रारा जारी को गई विधिक संध्रमूचपाण जिनमें प्रधि-				
भाग IIखण्ड 3उपखण्ड (i)-(रझा संत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों ग्रीर (सब राज्य क्षेत्रों के प्रशासनो		सूत्रनाएं, श्रादेश. विज्ञापन शोर नीटिस शामिल हैं .	1491			
को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के श्रन्तगंत उत्ताए भोर		भाग JV —गैर सरकारा व्यक्तियों ग्रौर गैर- सरकारो संस्थान्नो क विज्ञापन तथा नोटिस .	151			

CONTENTS

	PAGE		PAGE
Part I—Section 1.—Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the		(other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities other than the Administrations of Union Territories)	2069
Ministry of Defence) and by the Supreme Court	729	PART II—SECTION 3.—Sub. Sec. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministrics of the Government of India	
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other	•	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	2395
than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1193	PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	207
PART I—Section 3—Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders, and Resolutions issued by the Ministry of Defence	9	PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India.	5109
PART I—Section 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	861	PARTIII—Section 2-Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta	651
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	_	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	139
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills 1	-	PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory	
PART II—SECTION 3.—Sus. Sec. (i)—General Sta- tutory Rules (including orders, bys-laws		Bodies	1491
etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India		PART IV—Advertisements and Notices by Private individuals and Private Bodies	151

भाग I—**खण्ड** 1 [PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आवेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Kesolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विधि, न्याय श्रौर कम्पनी कार्य मंत्रालय

कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 19 घगस्त 1978

भ्रादेश

मं० 27 (26)/78-सी० एल०-2--कम्पनी - अधिनियम, (1956 का 1) की धारा 209क की उप-धारा (1) के खण्ड (2) के धनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतब्दारा कम्पनी कार्य विभाग में उप निवेशक (निरीक्षक) श्री ग्रार० ग्रधीरा मूर्ति को कथित धारा 209क के उद्देश्य के लिए प्राधिद्वत करती है।

केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा विभाग के घादेश संख्या 7 (11)/75-सी० एस०-2 दिनांक 15-11-75 द्वारा श्री ग्रार० ग्रधोरा मूर्ति उप-निदेशक (निरोक्षण) के पक्ष में पहले जारी किये गये प्राधिकरण का गिरसन करती हैं।

एस० बलरामन, भवर सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, विनाक 16 भगस्त 1978

संकल्प

- [(i) प्रारंभिक पैरा में "तम्बाकू का विषणन" शब्दों के बाव "वर्जीनिया तम्बाकू को छोड़कर" शब्द निकाल दिये जायेंगे।
- (ii) पैशा 1 के उप-पैरा (11) (ठ) में वी गई सदस्यों की सूची में "गुजरात" शब्द से पहले "म्नान्ध्र प्रदेश" जोड़ा जायेगा।
- (iii) पैरा 3 में पहले विचारार्थ विषय के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा:---

"छटी पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्जीनिया तस्वाकू, बीड़ी तस्वाकू य धन्य प्रकार के तस्वाकू की घरेलू मांग और साथ ही उनकी निर्यास मांग का धनुमान लगाना तथा छठी योजना धवधि के दौरान उस के धाधार पर विभिन्न प्रकार के तस्वाकू के उत्पादन लक्ष्यों भौर साथ ही विभिन्न राज्यों में क्षेत्रवार ऐसे तस्वाकू के धन्तर्गत लाये जाने वाले क्षेत्रों के बारे में भी सिफारिश करना"। [(iv) पैरा 3 में विचारार्थ विषय सं (iv) के बाद निम्नलिखित विचारार्थ विषय जोडा जायेगा :--

"तम्बाकू बोर्ड प्रधिनियम, 1975 में संगोधन करने की धावण्यकता की जांच करना व उन संगोधनों के बारे में सिफारिश करना जो उसके विचार में श्रिधिनियम में किये जाने चाहिए जिससे तम्बाकू बोर्ड देश में पैदा होने वाले सभी प्रकार के तम्बाकू के उत्पादन, अनुसंधान व विकास, विपणन व निर्यात के संबंध में निर्णायक भूमिका निभासके"।

भावेश

श्रावेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन तथा भारत सरकर के सभी मंत्रालयों, योजना भायोग, मंत्रिसंडल सचिवालय, प्रघान मंत्री के कार्यालय, लोक सभा व राज्य सभा सचिवालयों को मेजी जार्ये।

यह भी भादेश विया जाता है कि सामान्य सुचनार्थ संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

बी॰ सी॰ पांडे, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, विनांक 14 ग्रगस्त 1978

संकल्प

सं० 13 (6)/78-ई० पी० जैंड—भारत सरकार ने कांडला मुस्त ज्यापार क्षेत्र के विकास में बाघक समस्यामों का प्रध्ययन करने के लिए, संकल्प सं० 13(6)/78 ई० पी० जैंड दिनांक 29 जून, 1978 द्वारा स्थापित समिति के कार्यकाल को 29 जुलाई, 1978 से एक महीने की मबधि के लिए बढ़ाने का विनिश्चय किया है।

ग्रावेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और सभी राज्य सरकारों को भेजा जाए।

सुदर्शन सिंह, उप निदेशक

कृषि भौर सिंचाई मन्त्रालय

(कुषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 ग्रगस्त 1978

संकल्प

सं० 11-5/78-एल० डो०-1—विल्ली दुग्ध योजना की प्रवन्धक समिति इस मंत्रालय के संकल्प सं० 11-3/78--एल० डी०-1 दिनांक 19 धप्रैल, 1978 के द्वारा पुनर्गटित की गई थी।

- 2 यद्मिप यह धावस्यक समझा गया कि प्रबन्धक समिति को दूरगामी श्रायोजना भीर कार्यकारी निर्णयों के लिए पर्याप्त शावितया दी जाए ताकि दिल्ली दुग्ध योजना के प्रबन्ध तथा इसके कार्यक्रमो के श्रायोजन भीर कियान्वयन में बांछित सुधार लाया जा सके, तथापि सरकार ने कृषि ग्रीर सिंचाई महाला कृषि विभाग के सकल्प सं० 11-3/78-एल० डी०-1 दिनाक 19 श्रप्रैल, 1978 के श्रांशिक समोधन के रूप में यह निर्णय लिया है कि दिल्ली दग्ध योजना की प्रवन्धक समिति निम्नांकित कार्य तथा शक्तियो का प्रयोग करेगी -
 - (क) सभी नीति सबंधी मामलों पर विचार करना और स्वीकृति प्रदान करना, प्राथमिकताए निर्धारित करना ग्रौर योजना की श्रायस्यकताश्रो की पूर्ति के लिए वाछित मगठनात्मक परिवर्तन खाना :
 - (ख) सरकार के सम्मुख प्रस्तुतीकरण हेतु बजट की स्वीकृत करना;
 - (ग) जिन वार्षिक कार्यक्रमों में रबीकृति कार्यक्रमों की तुलना में निधियो के पूर्नियोजन की शक्तियो पर नियक्षण की सीमा में भारी माला में पुन.ग्रावटन शामिल है, उन पर विचार करके स्वीकृति प्रदान करना;
 - (घ) कर्मचारियो की व्यवस्था से सबधित मभी मामलो पर विचार व सिफारिश करना तथा उनको क्रियान्वित करना ;

- (इ.) प्रवन्त्रक समिति, जिली दाध रोजना ने सम्बाह किसी भी विषय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशो का ग्रनपालन क्यागी।
- (च) वित्तीय शक्तियो ना उपयान जा कि 1979 ने वितीय शक्तिया ता प्रदान करने करने नियमों के धन्तर्गत शलग से दी जाएगी।

आदण

भादेश दिया जाता है कि इस सकत्य की प्रति सभी राज्य सरकारो/ संघ राज्य क्षेत्र, भारत सरकार के सभी मक्षालय/विभाग, मन्द्रिमण्डल सनिवालय, प्रधान मत्नी सचिवालय/राष्ट्रपति सचिवालय, योजना श्रायोग भारत के नियन्नक श्रीर महालेखा परीक्षक, महावेखापाल केन्द्रीय राजस्य, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक, सचिव, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, **ग्रा**नन्द, गुजरात, सचिव, भारतीय डेरी: निगम, ब**डौ**दा, भारतीय **कृषि** भनुसंधान परिषद्, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, मेयर, निगम, श्रध्यक्ष, नई दित्ली नगर पालिका, महाप्रवन्धक, दिल्ली दूग्ध योजना ।

पी० एस० भ्रष्यु, भ्रपर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi, the 19th August 1978

ORDER

No. 27(26)78 C.L. II—In pursuance of clause (ii) of subsection (1) of section 209 A of the Companies Act, 1956 (I of 1956), the Central Government hereby authorises Shri R. Aghoramurthy, Deputy Director (Inspection) in the Department of Company Affairs, New Delhi for the purpose of the said section 209 A.

The Central Covernment hereby revolves the earlier authorises.

The Central Government hereby revokes the earlier authorisation issued in favour of Shii R. Aghoramurthy, Deputy Director (Inspection) vide Department's order No. 7(11)75 C.L. II dated 15-11-75.

S BALARAMAN, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 16th August 1978

RESOLUTION

No. 9/7/78-EP(AGRI.VI).—The Government of India, by resolution No. 9/7/78-EP(Agri. vi) dated 15th July, 1978 had set up an Expert Group for tobacco, other than vinginia tobacco. The Government have now decided to include virginia tobacco also in the terms of reference of the Group. Accordingly, the following amendments may be made in the resolution referred to above :-

- (1) In the opening paragraph after the marketing of tobacco", the words virginia tobacco" shall be deleted. "the words "other thin
- (ii) In the list of Members given in sub-para (ii)(L) of para. 1, "Andhra Pradesh" shall be added before the word "Gujarat".
- (iii) In para 3, the first term of reference shall be substituted by the following:—

"To make an assessment of the total domestic as well as export demand for virginia tobacco, bidi tobacco and other types of tobaccos during the Sixth Plan period and to recommend on that basis the production targets for different types of tobaccos and also the areas to be put under such tobaccos in various States area-wise, during the 6th Plan period".

(iv) In para 3 after terms of reference No (iv) the following new terms of reference will be added .-

> "to examine the need for amending the Tobacco Board Act, 1975 and to recommend the amendments which in its opinion should be made in the Act so as to enable the Tobacco Board to play a decisive tole in respect of production, research and development marketing and export of all types to tobaccos produced in the country.

ORDER

Oldered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments. Administration of Union Terretories and the Ministries of Government of India, Planning Commission, Cabinet Scretariat, Prime Ministries office, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats,

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. C. PANDE, Jt Secy.

New Delhi, the 14th August 1978

RESOLUTION

No 13(6)/78-EPZ.—The Government of India have decided to extend the term of the Committee set up vide Resolution No. 13(6)/78-FPZ dated the 29th June, 1978, to look into the problems which are hindering the growth of the Kandla Free Trade Zone, for a period of one month with effect from 29th July, 1978.

ORDER

Ordered that the Resolution may be published in the Gazette of India for general information and Communicated to all Ministries of the Government of India and all State Governments.

> SUDARSHAN SINGH, Dy. Director

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION (DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 19th August 1978 RESOLUTION

No. 11-5/78-LD.I.—The Management Committee of Delhi Milk Scheme was reconstituted vide this Ministry's Resolution No. 11-9/78-LD.I, dated the 19th April, 1978.

- 2. Whereas it is considered necessary to vest the Management Committee with adequate powers both for forward planning and executive decisions so as to enable it to bring about the desired improvement in the Management as well as the planning and execution of the programmes of the Delhi Milk Scheme, Government have been pleased to decide that in partial modification of Resolution No. 11-3/78-LD.I, dated 19th April, 1978 of Government of India, Ministry of Agriculture & Irrigation, Department of Agriculture, the Management Committee of D.M.S. shall perform the functions and exercise the powers given below:—
 - (a) consider and approve all policy matters, lay down priorities and introduce the organisational changes necessary to meet the requirements of the scheme;
 - (b) approve the Budget for presentation to the Government;
 - (c) consider and approve changes in the annual programmes, involving substantial reallocation of Funds in relation to the approved programme subject to restrictions on powers of reappropriation;

- (d) consider, recommend and implement policies regarding all matters pertaining to personnel management;
- (e) the Management Committee shall carry out such directives as the Government of India may issue from time to time on any matter pertaining to the D.M.S.
- (f) financial powers as may be separately delegated under the Delegation of Financial Powers Rules, 1978.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments/Union Territories, All Ministries/Departments of the Government of India, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, the President's Secretariat, the Planning Commission, the Comptroller & Auditor General of India, the Accountant General Central Revenues, the Director of Commercial Audit, Secretary, National Dairy Development Board, Anand, Gujarat, Secretary, Indian Dairy Corporation, Baroda, the Indian Council of Agricultural Research, the Director General of Health Services, Mayor, Delhi Municipal Corporation, the President, New Delhi Municipal Committee, the G.M., Delhi Milk Scheme.

P. S. APPU Addi, Secy. (AF)